VOL- XI | ISSUE- II | FEBRUARY | 2024 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 8.02 | ISSN 2349-638x

हनुमानगढ़ जिले में कृषि भूमि उपयोग संबंधी समस्याएं व समाधान

डॉ. अजय सिहाग
सह आचार्य (भूगोल)
डी.ए.वी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

सारांश

किस क्षेत्र की संपूर्ण भूमिका का विभिन्न कार्यों के लिए किये जाने वाले उपयोग को भूमि उपयोग की संज्ञा दी जा सकती है अर्थात धरातल का एक खंड या भाग जो पूर्व में वन क्षेत्र के रूप में या फिर परिवर्तन के साथ इसका परिवर्तित रूप कृषि और फिर सघन कृषि और अंत में तकनीकी कृषि के रूप में उपयोग होने वाला भाग पूरा परिवर्तन हुआ और एक बसाऊ क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये होने वाले परिवर्तन मानव के ज्ञान और उसकी प्रखर बुद्धिमता के कारण संभव होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ-साथ कुछ समस्याएं भी गतिमान हो जाती है या जन्म ले लेती है जोकि इन परिवर्तनों के लिए एक चुनौती के रूप में प्रकट होती है। जैसे-जैसे भूमि उपयोग का रूप परिवर्तन होता है उसी के साथ-साथ समस्याएं भी परिवर्तित रूप में प्रकट होती है कुछ ऐसी ही समस्या हनुमानगढ़ जिले में कृषि भूमि उपयोग से संबंधित है।

मुख्य शब्द- *भूमि उपयोग, सघन कृषि, व्यापार क्षेत्र, अनुदान, सिचाई, प्रशिक्षण, सुनियोजित*

प्रस्तावना-

मानवीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्त्व है। जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन एवं वन्य संसाधन पर दीर्घ काल तक निर्भरता के उपरांत मनुष्य धीरे-धीरे कृषि विधियों को अपनाने लगा और कालांतर में वही इन्हीं के द्वारा जीविकोपार्जन करने लगा। आज मानव के भरण-पोषण में कृषि का प्रमुख योगदान है। इसी पर आधारित अन्य व्यवसाय भी मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उसकी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक बन गए हैं। कृषि के प्रचलन ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति की है कृषि कार्य से मनुष्य के यायावर जीवन में स्थायित्व आया, उसे गृह निर्माण करना पड़ा तथा कृषि में पशु शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ एवं मनुष्य ने पशु चारण युग से वर्तमान अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। कृषि का श्रीगणेश भी मानव सभ्यता की भांति ही अति प्राचीन है मनुष्य ने आखेट वन क्रियाकलाप एवं पशुपालन के उपरांत ही कृषि कार्य प्रारंभ किया पशुचारण और कृषि कार्य दीर्घकाल तक साथ-साथ किंतु अर्थव्यवस्था रूप में चलते हैं, धीरे-धीरे कृषि कार्य प्रधान बनने लगा कृषि का प्राथमिक रूप बदलता रहा और आज वह अपने पूर्ण आधुनिक विकसित एवं व्यापारिक रूप में दिखाई देती है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य ने जंगलों को साफ किया और उसे कृषि में परिवर्तित कर दिया धीरे-धीरे नदी घाटियों के अतिरिक्त पठारो व मरूभूमियों में भी कृषि कार्य फैलता गया। गांव में नगरों का जाल सा बिछ गया और भूमि में एक निश्चित क्षेत्र से अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाने लगा। इस प्रकार आधुनिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक कारणों, शोधों व अध्ययनो की शुरुआत हुई।

अध्ययन क्षेत्र–

हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर में घग्घर नदी के दोनों तटों पर स्थित है नदी के उत्तर कि ओर टाऊन व दक्षिण की ओर जंक्शन स्थित है हनुमानगढ़ जिला २९°५' उत्तरी अक्षांश से ३०°६' उत्तरी अक्षांश व ७४° ३' पूर्वी देशांतर से ७५°३' पूवी देशान्तर के मध्य स्थित है। प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को युद्धेय कहा जाता था ।यहां एक प्राचीन किला है जिस का नाम भटनेर था भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है जिसका अर्थ भट्टी अथवा भाटियों का नगर है भारत के पश्चिम में स्थित होने के कारण इस किले को पश्चिम का पहरी भी कहा जाता है। यहां स्थित भटनेर दुर्ग को २८५ ईसा में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह भाटी ने बनवाया इसलिए इसे भटनेर कहा जाता है मंगलवार को दुर्ग की स्थापना होने के कारण हनुमान जी के नाम पर इस जिले को हनुमानगढ़ कहा जाता है।

इस जिले को १२ जुलाई, १९९४ को श्री गंगानगर से अलग करके इसे राजस्थान का ३१ वां जिला बनाया गया। इस जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा से लगती है यहां की कुल जनसंख्या ११७७४६९२ है जिसमें ९३११८४ पुरूष व ८४३५०८ महिला है। कुल जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या ३५०४६४ (१९.७५:)व ग्रामीण जनसंख्या १४२४२२८ (८०.२५:) है यहां राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा नहर का आरंभ यहीं से होता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में ७ तहसील, ७ उपखंड, ७ पंचायत समितियां, २५१ ग्राम पंचायत, १ नगर परिषद, ५ नगर पालिका, १८३१ आबाद ग्राम, व ३०३ पटवार वृत स्थित है।

उद्देश्य–

१. अध्ययन क्षेत्र मे कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी समस्याओ का परिकलन करना।
२. अध्ययन क्षेत्र में कृषि उपयोग को जानना व उनके समाधान का विश्लेषण करना।

परिकल्पना–

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में नहरी सिंचाई जल उपलब्ध होने के कारण यहां का आर्थिक तंत्र कृषि पर आधारित है जिस कारण यहां के भूमि उपयोग के तत्वों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है साथ ही उन समस्याओं के समाधानो का सर्जन किया गया है।

आंकड़ों के स्त्रोत–

प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन के लिए जिले के समस्त विकास खंडों को आधार माना है तथा आंकड़ों का संकलन जिला सांख्यिकी पुस्तिका कृषि विभाग एवं भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त किए हैं।

कृषि भूमि उपयोग संबंधी समस्याएं–

राजस्व जिला हनुमानगढ़ कृषि के क्षेत्र में राजस्थान का अग्रणी जिला है। जिले में ७ तहसीलें व ७ पंचायत समितियां है जिले में मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नहर घग्घर नदी, गंग कैनाल नहर, व राजीव गांधी सिधमुख नहर से सिंचाई होती है यहां की मुख्य फसलें कपास, ग्वार, बाजरा, गन्ना, गेहूं, जो, चावल, सरसों, चना आदि है। लेकिन जिले में उपयुक्त सिंचित जमीन तथा कृषि तकनीक होने के बावजूद भी कृषि समस्याएं रावण के १० सिरों के समान है। यदि एक समस्या का निदान किया जाता है तो दूसरी मुंह बाए खड़ी हो जाती है। अतः इनका समेकित संतुलित एवं सर्वग्राही निदान आवश्यक है अतः जिले में कृषि की प्रमुख समस्या निम्न है–

१. वर्षा की प्रकृति–

जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान में वर्षा की प्रकृति अनियमित,अनिश्चित, अपर्याप्त तथा अनोखी है जिले में किसी वर्ष वर्षा का औसत ३० सेमी होता है। वह दूसरे वर्ष १३ सेमी की होती है। इस प्रकार का यह परिवर्तन हनुमानगढ़ जिले की सभी तहसीलों में देखने को मिलता है वर्ष २०१८ में हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ तहसील मे २०.८० सेमी, पीलीबंगा में २३.४० सेमी,

संगरिया में २२.५० सेमी, टी.बी. में ३९.२० सेमी, नोहर में १५.९० सेमी, भादरा में ४०.१० सेमी वर रावतसर में ३०.५० सेमी वर्षा हुई जिले में वर्षा कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही प्रारंभ हो जाती है तो कभी अगस्त में भी वर्षा नहीं होती अतः यहां वर्षा की प्रकृति कृषि एवं कृषि विकास के लिए अद्वितीय समस्या है।

२. सिंचाई की सुविधाओं में कमी-

स्वतंत्रता के पश्चात् से जिले में सिंचाई की सुविधाओं में २१.९: की वृद्धि हुई है विशेषकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिले का काफी हिस्सा सिंचित क्षेत्र में आ गया है लेकिन यह क्षेत्र जिले के बोये गये क्षेत्र का मात्र ४०: ही है वर्तमान संदर्भ में नहरों में जल प्रवाह की बात की जाए तो एक व्यंग्य होगा इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले की अधिकांश खरीफ की फसलें वर्षा जल पर ही निर्भर करती है जबकि रबि की फसल कोसिचाई प्राप्त होती है।

३. जिले में भूमि व्यवस्था की कमी-

जिले में अधिकांश किसानों के पास या तो भूमि नहीं है या छोटे जोते हैं इस कारण कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी यंत्रीकरण राष्ट्रीय कृषि नीति आदि का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता भूमिहीन किसानों का बाहुल्य होने के कारण कृषि विकास योजना विफल रहती है

४. निर्धन कृषक-

कृषक के पास उन्नत बीज खरीदने,उर्वरको का प्रयोग करने, कीटनाशक दवाइयां खरीदने, यंत्र एवं उपकरण खरीदने, सिंचाई का प्रबंध करने भंडारण, अनुसंधान का लाभ लेने आदि के लिए धनराशि का सदैव अभाव रहता है अतः कृषि के विकास में कृषि की निर्धनता आड़े आती है इसलिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने इन कष्टों को विभिन्न प्रकार के ऋण सब्सिडी अनुदान आदि देकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया है सहकारी समितियों सहकारी बैंक नाबार्ड विश्व बैंक आदि से ऋण का प्रबंध कर किसानों की हालत सुधारी जा रही है।

५. कृषको में शिक्षा का अभाव-

जिले का कृषक वर्ग अधिकांश अनपढ़ है यहां की कुल साक्षरता २०११ के अनुसार ६७.१: है जिसमें पुरुष साक्षरता ७७.४: व महिला साक्षरता ५५.८: है यहां की शहरी साक्षरता की बात करें तो २०११ के अनुसार ७५.४: वह ग्रामीण साक्षरता मात्र ६५.१: है जिसके कारण यहां के कृषक कृषि अनुसंधान का लाभ प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं यंत्रीकरण का उपयोग नहीं कर पाता इसी कारण कृषि विकास धीमी गति से चल रहा है जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

६. कृषि उपजो के भंडारण एवं विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था-

जिले में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद जैसे मसाले, तिलहन, फ्रूट फसलें और अन्य फसलें पैदा होती है इनके भण्डारण एवं विपणन की जो व्यवस्था है पर्याप्त उचित प्रकार की नहीं है जिस कारण यहां के उत्पादन का सुरक्षित ,सरक्षित एवं उपयोगी भंडारण नहीं हो पाता और साथ ही साथ विपणन की कमी के कारण किसानों को समय पर उपज का उचित लाभ नहीं मिल पाता यही कारण है कि जिले में किन्नू माल्टा संतरा सरसों गेहूं कपास और सब्जियां खराब हो जाती है जिस कारण किसान को उचित राशि नहीं मिल पाती जो कि किसानों की एक बड़ी समस्या है।

७. कृषि फसलों के रोग-

जिले के कृषक अनभिज्ञ, अवैज्ञानिक और अप्रगतिशील व शीघ्र खराब होने के कारण फसलों के रोगों की रोकथाम के उपाय समय पर नहीं कर पाते इसी कारण खरीफ की फसलों का क्षय, लट, कातारा, दीमक, सुंडी आदि फसलों को खराब कर देते हैं और रबी की फसलों के रोग मौल्या, चौपा, आदि है जो यहां की फसलों को खराब करते हैं और कृषक वर्ग इनका उचित उपचार नहीं कर पाते यद्यपि मौसम विज्ञान कृषि वैज्ञानिक सूचना तंत्र सभी रोगों की रोकथाम के उपाय समय-समय पर सुझाव देते रहते हैं

८. मृदा सरक्षण क्षारीयतार एवं अम्लीयता की समस्या–

मृदा का कटाव एक रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा के रूप में देखी जाती है मृदा का कटाव, मृदा प्रदूषण, मृदा उपचार एक बहुत बड़ी समस्या है जिले के कुछ भाग में मरुस्थलीकरण की समस्या है जिस कारण रेत के फैलाव,शुष्कता आदि के कारण मृदा का क्षरण होता है क्षारीयता, अम्लता भी जिले की भूमि की विकट समस्या है भूमिगत जल के क्षारीय होने के कारण क्षारीयता बहुत बढ़ गई है।अम्लता का अश मृदा मैं फसलों के उत्पादन को कम कर देता है भूमि को बंजर बना देता है।

९. जोतों का आकार छोटा होना–

जिले का अधिकांश किसान लघु व सीमांत श्रेणी का है जोतों का आकार छोटा होने के कारण वह उन्नत तकनीकी यंत्रों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर सकता है अतः जोतो का आकार बढाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं भूमि सुधार कानून बनाए जा रहे हैं उनका उचित प्रचलन होना आवश्यक है।

१०. सेम की समस्या–

इस क्षेत्र में भाखड़ा नहर से ६७.६४ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में व इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिले में ५४.८७ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है पिछले काफी वर्षों से घग्घर नदी में खड़े पानी,नाली में बाढ़ के पानी वनहरों तथा सिंचित क्षेत्र से लगातार रिसाव के सम्मिलित परिणाम तथा सतही व भूजल स्तर तेजी से ऊपर उठा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के बाद रावतसर पीलीबंगा तहसील का जल स्तर १०० फीट से भी अधिक कौन सा उठा है जिससे इस क्षेत्र में जल प्लावन की स्थिति पैदा हो गई है। इस क्षेत्र में भूजल का स्तर काफी तेजी से ऊपर उठा है नहरों वसिंचाई मेंरिसाव की मात्रा ,क्षेत्र से जल निकासी की मात्रा अधिक होने व भूजल ऊपर आ जाने से जल प्लवन व लवण की समस्या पैदा होती है।इस क्षेत्र में घग्घर में बाढ़ से आने वाले ने भी इस समस्या मे विशेष योगदान है

समाधान व उपाय–

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने भरकश प्रयत्न किए हैं जो इस प्रकार है –

१. प्राकृतिक आपदाओं यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, पाला, वृष्टि आदि प्राकृतिक विभिन्न प्रकोपों से निपटने के लिए सरकार ने सिंचाई का प्रबंध विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं एवं जल प्लावन के बाढ़ के पानी को स्वीकार बांधो आदि में रोककर आंधी, पाला एवं ओलावृष्टि की पूर्व मौसम संबंधी सूचना देकर किसानों को सतर्क कर के, भूरक्षण संबंधी विभिन्न कार्य संपादित करके ,वृक्षारोपण ,मेड़बंदी आदि करके तथा कीटनाशकों द्वारा फसलों के रोगों को बचाकर कृषि को गति दी है।

२. सिंचाई की लघु एवं मध्य परियोजनों द्वारा किसानों को यथाशीघ्र लाभ देकर, सिंचाई द्वारा अधिक उत्पादन करके कृषि विकास को गति दी जा सकती है।

३. भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था को दूर करके भूमि सुधारों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया गया है सीलिंग कानून भूमि सुधार कानून खातेदारी अधिकार देकर तथा जमीदारी प्रथा जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर कृषि उत्पादन को गति प्रदान की गई है।

४. राज्य में कृषक को बैंक,संस्थाओं वसहकारी समितियों के माध्यम से कृषि यंत्र बीज उर्वरक कीटनाशक आदि खरीदने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान कर एक नए अध्याय की शुरुआत की है जिससे उन्नति के आसार सामने आए हैं।

५. कृषि षिक्षा, कृषि विस्तार, कृषि प्रदर्शन एवं कृषि प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संपूर्ण कृषक वर्ग लाभान्वित हुआ है एवं उसके परिणाम स्वरूप कृषि कार्य और उसके क्रियान्वयन हेतु नए आयाम जुड़े हैं। कृषकों को मिनी किट्स

वितरण किए गए हैं, जिससे सीमांत कृषक एवं लघु कृषक लाभ उठाकर कृषि की प्रगति में भागीदार बन सके हैं

६. उन्नत बीज प्रमाणित बीज आकार बीज वितरण कर सरकार एक अनूठा कार्य किया है काजरी ने इस दिशा में अद्वितीय कदम उठाया है सन २०१२-१३ में बाजरे का ६४०० किलोग्राम, चावल का १४६२०० किलोग्राम गेहूं का ११०६४७०० किलोग्राम, सरसों का ४५०० किलोग्राम, चने का ८६०५० किलोग्राम, तथा जौं ७८३० किलोग्राम बीज का वितरण किया गया।

७. कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कृषि की विभिन्न जिंसों का समर्थित मूल्य निर्धारित करना, जिले में मंडी नियंत्रण एवं भंडारण की व्यवस्था करना, मूल्य नीति को प्रभावी बनाना आदि कृषि को विकसित करने की ओर जिले के मील के पत्थर साबित होंगे।

८. जिले में उवर्रको के उत्पादन वितरण को बढ़ावा देकर उर्वरको का प्रभावी वितरण एवं प्रयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। उर्वरको का उत्पादन ही हर वर्ष नहीं बढ़ा है वरन उर्वरकों का प्रयोग भी बढा है २०१२-१३ में फसलों के लिए नाइट्रोजन ११६२५१ मै. टन, फास्फेटिक ५६८६१ मै. टन, पोटेशियम ४३५ मै. टन का वितरण किया गया जो जिले में कृषि विकास व उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हुआ।

इसके अतिरिक्त जिले में कृषि विकास व विस्तार के लिए सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख है राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम ,राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना, खरीफ व रबी अभियान, कृषि ज्ञान शिविर आदि के माध्यम से जिले में कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है ।

९. शोध जिले में बढ़ रही सेम समस्या के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए जिसमें स्थानीय काश्तकार ,सिंचाई विभाग एवं विकास विभाग के अधिकारीगण एवं भू वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व हो तथा यहां मिट्टी की गुणवंता का परीक्षण करके मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप कार्य योजना बनाई जाए, जिससे सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य में बदला जा सके।

निष्कर्ष-

शोध जिले में कृषि भूमि उपयोग में नहरी सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्र में भूमि उपयोग सुधार के लिए कृषि विस्तार सेवाओं के अधिकारियों ,ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों का कृषकों एवं कृषि कार्यकर्ताओं मैं लगातार और सघन संपर्क बढ़ाना आवश्यक है। उन्हें प्रदर्शन नमूना प्रस्तुत करके उनकी विश्वसनीयता में वृद्धि करना जरूरी है इसके साथ ही लघु कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र आदि यथासंभव अनुदान पर अथवा कम मूल्य .पर उपलब्ध करवाना ,उत्पादन वृद्धि में सहायक होना आदि कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे जिले की भूमि उपयोग सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

संदर्भ

1. राय, श्रीराम (१९७८) : शाहाबाद (बिहार) में भूमि उपयोग, उत्तर-भारत भूगोल पत्रिका अंक १४, संख्या २, पृष्ठ १२८-१३४
2. सिंह, बी.वी. एवं सिंह एस.जी. (१९७४) : शस्य समिश्रण विधि अध्ययन में एक पुनर्विलोकन उत्तर-भारत भूगोल पत्रिका अंक १०, संख्या १-२, पृष्ठ १-४
3. सिंह रामबली एवं पाण्डेय, श्रीकान्त (१९७०) फरेन्दा तहसील में जनसंख्या घनत्व एवं भू वैन्यासिककालिक विष्लेषण, उत्तर भारत का भूगोल पत्रिका, अंक १५, संख्या २, पृष्ठ १२१

4. Singh, B.N. (1975): Modernization of India Agriculturas High Yielding Varieties and Green Revolution Research Bulletin Nol. Eastrern Geography Society Bhxbanewar Corissa P- 09
5. Sharma, K.K. (1972) : Rajasthan Diostrict. Gazeteer, Jaipur. Districit Gazeteer of Rajasthan.
6. Chouhan D.S. Studies in the utilization of Agricultural Land. Ist: Pd (1966) P-48
7. Govt. of India : Co-odination of Agricultural Statstics in India, Minstry of Agriculture (1960), P-144
8. Statistical Report, Hanumangarh (Raj.)

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com